राष्ट्रीय उपभोक्ता जागरूकता समूह (रजि.) बनाम भारत संघ और अन्य (स्वतंत्र कुमार, जे)

समक्ष स्वतंत्र कुमार और राजीव भल्ला, न्यायमूर्ति

राष्ट्रीय उपभोक्ता जागरूकता समूह (पंजीकृत)-प्रार्थी

बनाम

भारत संघ और अन्य - प्रतिवादी

2004 का सी.डब्ल्यू.पी. नंबर 174

27 मई, 2004

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 - धारा 16 (1) (ए) और 16 (1) (बी) और 16 - ए (2002 के संशोधन अधिनियम संख्या 62 द्वारा अन्तर्स्थापित)- अध्यक्ष, राज्य आयोग-विलंब-जनहित याचिका-धारा 16(1)(क) में यह प्रावधान है कि अध्यक्ष की कोई नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद किए जाने के बिना नहीं की जाएगी।"- इसका अर्थ और दायरा कहा गया है, "परामर्श" राज्य पर मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेने का दायित्व डालता है। और इसे उचित वरीयता के साथ स्वीकार करें, सिवाय बहुत ही बाध्यकारी कारणों को छोड़कर- राज्य सरकार उस घटना में अपने अधिकार की सीमाओं को पार नहीं करेगी, भले ही वह नियुक्ति के लिए दूसरा नाम सुझाए-राज्य को अपना दृष्टिकोण रखने और मामले को पुनर्विचार के लिए सीजे को भेजने का अधिकार है - यदि सीजे द्वारा सिफारिश दोहराई जाती है तो राज्य सरकार सीजे द्वारा व्यक्त किए गए विचार को प्रभावी करने के लिए बाध्य है। अधिनियम की धारा 16(1)(क) के उपबंधों में कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं - राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए धारा 16(1)(क) के अधीन प्रदत्त सांविधिक योजना पर धारा 16 के संशोधित उपबंधों का कोई प्रभाव नहीं - राज्य आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति शीघ्र और निर्णय के एक माह के भीतर करने के लिए सभी कदम उठाने का निदेश दिया गया है।

यह निर्धारित किया गया, स्पष्ट शब्दों में परामर्श स्पष्ट रूप से उद्देश्यपूर्ण होगा और आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति पर विचार करते समय मुख्य न्यायाधीश के विचार को अनिवार्य रूप से प्राथमिकता दी जानी चाहिए। परामर्श राज्य पर एक दायित्व डालता है कि वह मुख्य न्यायाधीश की सलाह ले और इसे उचित वरीयता के साथ स्वीकार करे जब तक कि राज्य के पास सुझाए गए नाम पर पुनर्विचार के लिए मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करने के लिए बाध्यकारी कारण न हों। राज्य उस घटना में अपने अधिकार की सीमाओं को पार नहीं करेगा, भले ही वह

आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए किसी अन्य नाम का सुझाव दे। यदि मुख्य न्यायाधीश के अंत में इस पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाती है, तो यह अधिनियम के उद्देश्य के साथ-साथ निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से पूरा करेगा। वरीयता एक मूल्यवान शब्द है और इसे निष्पक्ष रूप से समझा जाना चाहिए।

(पैरा 20)

इसके अलावा, विभिन्न विचारों की संभावना को समाप्त नहीं किया जा सकता है, खासकर जब यह अच्छे और वैध कारणों से हो। विचारों में मतभेद, यदि कोई हो, को आपसी चर्चा, उद्देश्यपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण से हल किया जाना चाहिए। लेकिन, किसी भी मामले में, राय की इस मृत ताले को तोड़ने के लिए संकेत दिया जाना चाहिए। हमारी राय में, आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में अंतिम निर्णय मुख्य न्यायाधीश के पास होना चाहिए। बिना किसी ठोस कारण के मुख्य न्यायाधीश की राय को नीचा दिखाना एक उचित कार्य नहीं होगा और इसके परिणामस्वरूप न्यायपालिका की गरिमा भी कम होगी और पूरी संभावना है कि न्याय के उचित प्रशासन में बाधा उत्पन्न होगी।

(पैरा 22 & 23)

इसके अलावा, धारा 16 (1) (ए) के प्रावधान स्पष्ट हैं और उनकी भाषा में इतने स्पष्ट हैं कि कानून के अनुरूप उनका कार्यान्वयन किसी भी तरह से मुश्किल या अव्यवहारिक नहीं होगा। अधिनियम की धारा 16(1-क) के बल पर उपबंधों के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न करने से संविधि के उद्देश्य, न्यायपालिका की स्वतंत्रता विफल हो जाएगी और अवांछनीय परिणाम प्राप्त होंगे। संशोधित धारा के प्रावधानों को केवल आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। धारा 16 (1) (ए) आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करती है और ये इस संबंध में मूल प्रावधान हैं। धारा 16 (1 ए) के प्रावधान किसी भी मामले में नियामक और प्रक्रियात्मक हैं। वे एक पद्धति का प्रावधान करते हैं, जिसे आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए अपनाया जाना चाहिए, एक बार जब राष्ट्रपति की नियुक्ति धारा 16 (1) (ए) के प्रावधानों के अनुरूप की जाती है, तो यह स्पष्ट रूप से अन्य प्रावधानों का भी पर्याप्त अनुपालन होगा।

(पैरा 38)

इसके अलावा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून की महिमा निश्चित रूप से यह परिकल्पना करती है कि आयोग के अध्यक्ष के न्यायिक

मंच पर नियुक्ति अधिनियम की धारा 16 (1) (ए) के प्रावधानों के अनुरूप की जानी चाहिए, जिसमें मुख्य न्यायाधीश की राय को निश्चित प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस पद के लिए प्रस्ताव आम तौर पर मुख्य न्यायाधीश द्वारा शुरू किया जाना चाहिए, ताकि नियुक्तियों में अनावश्यक देरी से बचा जा सके। इस नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल दो आवश्यक घटकों यानी मुख्य न्यायाधीश और राज्य के बीच प्रशासनिक सामंजस्य को इस प्रतिष्ठित पद पर सबसे उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कानून और पारस्परिकता के सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना चाहिए।

(पैरा 42)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजेश बिंदल और अधिवक्ता राकेश के. नागपाल पेश हुए।

हरियाणा के एडवोकेट जनरल अशोक अग्रवाल के साथ हरियाणा के डीएजी जेएस सिद्धू।

उत्तरदाताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एम. एल. सरीन, एच. एस. ज्ञानी और हेमंत सरीन, अधिवक्ता।

निर्णय

स्वतंत्र कुमार, न्यायमूर्ति

(1) राष्ट्रीय उपभोक्ता जागरूकता समूह (रजि.) को बाद में संगठन के रूप में संदर्भित किया गया है, याचिकाकर्ता, चंडीगढ़ में अपने प्रधान कार्यालय के साथ भारत सरकार द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त एक स्वैच्छिक संगठन होने का दावा करता है। यह संगठन 1998 से कार्य कर रहा है और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली राज्यों के विभिन्न शहरों में इसके उप-कार्यालय हैं। संगठन ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत यह याचिका दायर की है, जिसमें परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करने की प्रार्थना की गई है, जिससे उत्तरदाताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 16 के तहत हरियाणा राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चंडीगढ़ के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया जा सके।

(2) याचिकाकर्ता-संगठन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत सोसायटी है। याचिका में, संगठन ने शायद ही किसी व्यक्ति विशेष के तथ्यों का उल्लेख किया है, लेकिन संयुक्त रूप से इस न्यायालय से इस आधार पर उपरोक्त राहत का दावा किया है कि 4 सितंबर, 2003 को सेवानिवृत्त हुए न्यायमूर्ति अमरजीत चौधरी की सेवानिवृत्ति के बाद, आयुक्त का पद खाली पड़ा है और नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल कोई भी व्यक्ति अधिनियम के उद्देश्यों से

चिंतित नहीं दिख रहा है। संशोधित अधिनियम की योजना के अनुसार, समिति द्वारा प्रक्रिया पहले से शुरू की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता के अनुसार धारा 13 और 16 के संशोधित प्रावधानों और नई धारा 16 (1-ए) को शामिल करने के प्रभाव से राज्य आयोग के सदस्यों के नाम की सिफारिश के लिए एक चयन समिति की परिकल्पना की गई है। न केवल सदस्य बल्कि धारा 16 की उपधारा (1) के तहत प्रत्येक नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उन प्रावधानों में किए गए प्रावधान के अनुसार चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी। उनका दावा है कि राज्य आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत पहले शुरू की जानी चाहिए थी और अत्यधिक देरी से बड़े पैमाने पर जनता को असुविधा हो रही है और संशोधित अधिनियम के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के किसी भी प्रयास की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(3) वर्ष 2003 की सीडब्ल्यूपी संख्या 17262 के रूप में एक अन्य रिट याचिका श्री धरमिंदर सिंह रावत द्वारा दायर की गई है, जो इस उच्च न्यायालय में वकालत कर रहे हैं, लेकिन इस विचार पर जोर देते हुए कि कार्यपालिका को ऐसी नियुक्तियों के लिए मुख्य न्यायाधीश से संपर्क करना चाहिए और की गई नियुक्तियों को अधिक विश्वसनीयता देने के लिए न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया उसी तरह शुरू की जानी चाहिए। आशीष हांडा बनाम भारत संघ (1)[1] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर याचिकाकर्ता द्वारा निर्भता राखी गई, इन परिसरों पर याचिकाकर्ता प्रार्थना करता है कि प्रतिवादियों को न्याय के हित में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हरियाणा के अध्यक्ष को शीघ्र नियुक्त करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। दोनों रिट याचिकाओं में उच्च न्यायालय और राज्य सरकार द्वारा सामूहिक रूप से अपनाए गए रुख का उल्लेख करना उचित होगा। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा 26 अगस्त, 2003 को दायर लिखित वक्तव्य के अनुसार। माननीय मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के अध्यक्ष से दिनांक 25 अगस्त, 2003 को हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को संबोधित एक फैक्स प्राप्त हुआ, जिसमें इस आशय की सूचना दी गई थी कि चूंकि राज्य आयोग के अध्यक्ष श्री न्यायमूर्ति अमरजीत चौधरी 4 सितंबर, 2003 को सेवानिवृत्त हो गए थे, इसलिए राज्य आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की जानी चाहिए। इस प्रकार, तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। उसी दिन, मुख्य न्यायाधीश को एक माननीय न्यायाधीश के बायोडेटा के साथ सम तिथि का पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उनसे जल्द से जल्द अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया था। प्रधान न्यायाधीश ने सरकार को सूचित किया कि इस संबंध में प्रस् ताव शुरू करने के लिए उनके कॉलेजियम की बैठक जल् द ही होगी। कॉलेजियम की बैठक 27 अगस्त, 2003 को हुई, जिसमें नामों पर विचार किया गया और हरियाणा कैडर के एक सेवानिवृत्त

(1) AIR 1996 S.C. 1308

न्यायाधीश को नियुक्ति के लिए अधिक उपयुक्त और उपयुक्त पाए जाने के बाद उनके नाम की सिफारिश की गई। बदले में, दिनांक 29 अक्तूबर, 2003 के पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री ने मुख्य न्यायाधीश से अपनी सिफारिशों पर पुनवचार करने का अनुरोध किया। कॉलेजियम ने फिर से इस मामले पर विचार किया और एक राय बनाई कि जब तक सिफारिश को स्वीकार करने में मुख्यमंत्री की असमर्थता के कारणों का खुलासा नहीं किया जाता, तब तक सिफारिशों पर फिर से विचार करना संभव नहीं होगा। 1 दिसम्बर, 2003 को कुछ कारणों का खुलासा किया गया था। कॉलेजियम की 3 दिसम्बर, 2003 को पुन बैठक हुई, जिसमें कुछ तथ्यों का उल्लेख किया गया और उच्च न्यायालय को आशा थी कि नियुक्ति शीघ्र ही हो जाएगी और उसने अनुरोध किया कि रिट याचिका को खारिज कर दिया जाए।

(4) राज्य की ओर से दिनांक 17 दिसम्बर, 2003 को एक संक्षिप्त हलफनामा दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि न्यायालय के समक्ष अभिलेख प्रस्तुत किए गए थे। हालांकि, राज्य की ओर से एक विस्तृत जवाब 2003 की रिट याचिका संख्या 17262 में फिर से दायर किया गया था। यह विवादित नहीं है कि राज्य सरकार ने एक अन्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नाम का प्रस्ताव किया था और मुख्य न्यायाधीश से प्रस्तावित नाम के अनुमोदन से अवगत कराने का अनुरोध किया था। राज्य का रुख 2004 के सीडब्ल्यूपी नंबर 174 में याचिकाकर्ता के मामले के समान है। यह कहा गया है कि संशोधित अधिनियम के प्रावधानों के संयुक्त पठन के अनुसार, 2002 के संशोधन अधिनियम संख्या 62 द्वारा शामिल धारा 16 (1-ए) के तहत परिकल्पित चयन समिति, पहले राज्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र पूर्व या वर्तमान माननीय न्यायाधीश के नाम की सिफारिश करेगी और उसके बाद, उक्त नामों को परामर्श के लिए राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्य न्यायाधीश को भेजा जाएगा। यह कहा गया है कि राज्य आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति अधिनियम की धारा 16 (1-ए) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही की जा सकती है।

(5) भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 12 नवम्बर, 2003 के पत्र के लिखित विवरण के अनुलग्नक आरआईजेड पर भी निर्भारता रखी गई, जिसमें सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया था। विचाराधीन पद का उल्लेख करते हुए यह रुख अपनाया गया है कि उच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने 27 अगस्त, 2003 को हुई अपनी बैठक में यह दर्शाया था कि तीन नामों में से केवल एक में योग्यता पर विचार किया गया था और विचाराधीन अन्य दो नामों पर गुण-दोष के आधार पर इस कारण विचार नहीं किया गया था कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश में से एक को पंजाब बार का सदस्य बनाया जा रहा था और एक अन्य माननीय न्यायाधीश के मामले में। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय उस समय उनकी सेवाओं को छोड़ना पसंद नहीं करते थे। आयोग के दो सदस्यों

को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहा जाता है और आयोग के दिन-प्रतिदिन के काम उनके द्वारा देखे जा रहे हैं।

(6) उच्च न्यायालय की ओर से पेश वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा 2003 के सीडब्ल्यूपी संख्या 17262 में दायर लिखित बयान को अन्य रिट याचिका में भी लिखित बयान के रूप में पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि दोनों रिट याचिकाओं में एक सामान्य प्रश्न शामिल है।

(7) भारत संघ ने 2004 के सीडब्ल्यूपी संख्या 174 में लिखित बयान दायर किया और यह रुख अपनाया कि अधिनियम की धारा 16 (1) और 16 (1-ए) के प्रावधानों को संशोधित किया गया है और अधिनियम में पेश किया गया है और नियुक्ति उनके अनुरूप की जानी चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जिला और राज्य आयोगों की स्थापना करना और राष्ट्रपति और सदस्यों की नियुक्तियों सहित पर्याप्त बुनियादी ढांचा स्टाफ प्रदान करके उनके प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। यह उल्लेख किया गया है कि कुछ राज्य सरकारों ने अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के मद्देनजर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष के चयन के तरीके के बारे में प्रतिवादी संख्या 1 से स्पष्टीकरण मांगा था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का समान रूप से पालन किया जाए। दिनांक 31 दिसम्बर, 2003 के पत्र के माध्यम से अनुलग्नक डब्ल्यूआई, भारत संघ ने स्पष्टीकरण जारी किया था। दिनांक 31 दिसम्बर, 2003 के पत्र में निम्नानुसार लिखा गया है —

> "कुछ राज्य सरकारों ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष के चयन के तरीके के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। इसलिए, संशोधित अधिनियम के उपबंधों के अनुसार स्थिति को आपके ध्यान में लाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का समान रूप से पालन किया जाए।"
>
> 2. धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बिना अध्यक्ष, राज्य आयोग के पद के लिए कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती है।
>
> 3. अधिनियम की धारा 16 (1 ए) के प्रावधानों के अनुसार, धारा 16 के तहत की गई नियुक्तियों के लिए चयन समिति की अध्यक्षता राज्य आयोग के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। यह भी प्रावधान किया गया है कि जहां राज्य आयोग का अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा, चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने में असमर्थ है, राज्य सरकार अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान

न्यायाधीश को नामित करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भेज सकती है। इस खंड का उपयोग वहां भी किया जा सकता है जहां राज्य आयोग का अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र है और इस कारण से, वह चयन समिति की अध्यक्षता नहीं कर सकता है।

4. अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधान को जब राज्य आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति को ध्यान में रखते हुए रखा जाए।

आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।"

(8) हमारे समक्ष उठाए गए प्रस्तुतियों के गुण-दोष पर सांविधिक उपबंधों के प्रभाव की जांच करने के लिए, उन उपबंधों की भाषा का उल्लेख करना आवश्यक हो सकता है जो निम्नानुसार है:—

"16. राज्य आयोग की संरचना (1) प्रत्येक राज्य आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा:—

a. एक व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, जो इसका अध्यक्ष होगा:

[बशर्ते कि इस खंड के तहत कोई नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बिना नहीं की जाएगी।

b. कम से कम दो, और सदस्यों की ऐसी संख्या से अधिक नहीं, जैसा कि विहित किया जाए, और जिनमें से एक महिला होगी, जिसके पास निम्नलिखित योग्यताएं होंगी, अर्थात् :—

- पैंतीस वर्ष से कम उम्र का नहीं;
- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री; और
- क्षमता, अखंडता और स्थिति के व्यक्ति हों, और अर्थशास्त्र, कानून, वाणिज्य, लेखा, उद्योग, सार्वजनिक मामलों या प्रशासन से संबंधित समस्याओं से निपटने में कम से कम दस साल का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव हो।

बशर्ते कि पचास प्रतिशत से अधिक सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों में से नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "न्यायिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति" शब्द का अर्थ उन व्यक्तियों से होगा जिनके पास जिला स्तर के न्यायालय या समकक्ष स्तर पर किसी न्यायाधिकरण में पीठासीन अधिकारी के रूप में कम से कम दस वर्षों की अवधि के लिए ज्ञान और अनुभव होगा।:

बशर्ते कि किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि वह-

- उसे एक ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसमें राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता शामिल है; नहीं तो
- वह दिवालिया हो चुका है; या अस्वस्थ मन का है और सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है; या
- सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले कॉर्पोरेट निकाय की सरकार की सेवा से हटा दिया गया है या बर्खास्त कर दिया गया है; नहीं तो
- राज्य सरकार की राय में, ऐसा वित्तीय या अन्य हित, जो सदस्य के रूप में उसके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना है; या
- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले ऐसे अन्य प्रावधान हैं।

[(1-क) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित सदस्यों वाली चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी,

अर्थात्:—

- राज्य आयोग के अध्यक्ष;
- राज्य के कानून विभाग के सचिव सदस्य
- राज्य में उपभोक्ता मामलों से संबंधित विभाग के सदस्य सचिव

परन्तु जहां राज्य आयोग का अध्यक्ष, अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा, चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने में असमर्थ है, राज्य सरकार अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए उस उच्च न्यायालय के किसी पीठासीन न्यायाधीश को नामित करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास भेज सकती है।

(I-B) (i) राज्य आयोग की क्षेत्राधिकार, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग उसके न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा।

(ii) राष्ट्रपति द्वारा एक या अधिक सदस्यों के साथ एक पीठ का गठन किया जा सकता है जिसे राष्ट्रपति उचित समझे।

(iii) यदि किसी पीठ के सदस्यों की किसी बात पर राय भिन्न होती है, तो बिंदुओं का निर्णय बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा, यदि

बहुमत है, लेकिन यदि सदस्य समान रूप से विभाजित हैं, तो वे उन बिंदुओं या बिंदुओं को बताएंगे जिन पर वे भिन्न हैं, और राष्ट्रपति को एक संदर्भ देंगे जो या तो बिंदु या बिंदुओं को स्वयं सुनेंगे या ऐसे बिंदु या बिंदुओं पर सुनवाई के लिए मामले को भेजेंगे। एक या अधिक या अन्य सदस्य और ऐसे बिंदु या बिंदु मामले को सुनने वाले अधिकांश सदस्यों की राय के अनुसार तय किए जाएंगे, जिनमें वे भी शामिल हैं जिन्होंने इसे पहली बार सुना था।

(2) राज्य आयोग के सदस्यों को देय वेतन या मानदेय और अन्य भत्ते, और सेवा के अन्य नियम और शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएं:

(बशर्ते कि पूर्णकालिक आधार पर किसी सदस्य की नियुक्ति . राज्य सरकार द्वारा राज्य आयोग के अध्यक्ष की सिफारिश पर ऐसे कारकों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी जो राज्य आयोग के कार्य भार सहित निर्धारित किए जा सकते हैं।

[(3) राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य पाँच वर्ष की अवधि के लिए या सत्ताईस वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा:

परन्तु कोई सदस्य पांच वर्ष की एक और अवधि के लिए या सत्ताईस वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, इस शर्त के अधीन पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख) में उल्लिखित नियुक्ति के लिए अर्हताओं और अन्य शर्तों को पूरा करता है और ऐसी पुनर्नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है:

बशर्ते कि राज्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति भी इस धारा की उपधारा (1) के खंड (ए) में प्रदान की गई रीति से पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

बशर्ते कि कोई सदस्य राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर के साथ लिखित रूप में अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्यागपत्र स्वीकार किए जाने पर उसका पद रिक्त हो जाएगा और उसे उप-धारा 1 में उल्लिखित किसी भी योग्यता रखने वाले व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरा जा सकता है। उस सदस्य की श्रेणी के संबंध में जिसे इस्तीफा देने वाले व्यक्ति के स्थान पर उप-धारा (1-ए) के प्रावधानों के तहत नियुक्त किया जाना आवश्यक है।

(4) उपधारा (3) में निहित किसी बात के होते हुए भी, उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारंभ होने से पूर्व राष्ट्रपति के रूप में

या सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपने कार्यकाल के पूरा होने तक अध्यक्ष या सदस्य, जैसा भी मामला हो, ऐसे पद पर बना रहेगा।

(9) प्रारंभ में और इससे पहले कि हम वर्तमान रिट याचिका में शामिल कानून के जटिल प्रश्नों के गुण-दोष पर विचार करें, हम देख सकते हैं कि ये दोनों रिट याचिकाएं जनहित याचिकाओं के रूप में दायर की गई हैं। जाहिर है, उनके पास उचित दस्तावेज द्वारा समर्थित निश्चित और विस्तृत दलीलों की कमी है। इस प्रकार, यह सटीक कारण है कि इस न्यायालय की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश क्यों दिया था।

(10) राज्य आयोग की संरचना की जांच प्रक्रिया, नियुक्ति और मध्यवर्ती चरण से संबंधित प्रासंगिक प्रावधानों को देखकर की जा सकती है जहां विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों को एक निश्चित भूमिका निभाने की आवश्यकता होती है। अधिनियम और विशेष रूप से अधिनियम का अनुच्छेद 16 अपने आप में एक संपूर्ण प्रक्रिया है और इस प्रकार, हमें इस धारा की व्याख्या से निपटने की आवश्यकता होगी ताकि प्रक्रिया और कार्यप्रणाली को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया जा सके जिसका विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों से अनुसरण करने की अपेक्षा की जाती है।

<u>राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के लिए धारा 16(1)(ए) में दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति "उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद को छोड़कर" का दायरा और व्याख्या -</u>

(11) पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हमें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए, वह अभिव्यक्ति का अर्थ और दायरा है "उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को छोड़कर"। अधिनियम की धारा 16 (-1) (ए) के इस परंतुक की भाषा अस्पष्टता से मुक्त है और स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि विधायिका द्वारा व्यक्त निश्चित विधायी इरादा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के दृष्टिकोण को दिए जाने वाले महत्व को दर्शाता है। विधायिका ने अपने विवेक से इस शब्द का इस्तेमाल किया है कि "इस खंड के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के अलावा कोई नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श अनिवार्य है, जिसके लिए कोई अपवाद नहीं है।

(12) "मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श" की अभिव्यक्ति को व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए और एक अर्थ जो परिणाम में प्रभावी है। अभिव्यक्ति को आम बोलचाल में इसकी समझ के विपरीत स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए। यह निश्चित रूप से सलाह, राय या औपचारिक अनुमोदन लेने जैसा नहीं है। न्यायिक निर्णयों में व्यक्त किए गए सुसंगत दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह इसके अर्थ और अवधारणा को सही परिप्रेक्ष्य में समझे। अभिव्यक्ति से यह पता नहीं चलता है कि राज्य अपने विधि अधिकारी (अधिकारियों) से परामर्श कर रहा था, जिनकी राय

को वह कानून के मामले में भी स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश के पद की गरिमा के लिए राज्य को मुख्य न्यायाधीश के दृष्टिकोण को निश्चित वरीयता के साथ समझने और उक्त राय को दरकिनार करने के तरीकों और साधनों को खोजने का प्रयास किए बिना इसे प्रभावी बनाने की आवश्यकता होती है। इस तरह के दृष्टिकोण की न तो वैधानिक रूप से अनुमति है और न ही न्यायिक घोषणाओं द्वारा।

उच्चतम न्यायालय के समक्ष कई अवसरों पर विचारार्थ परामर्श शब्द आया था और देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार को समय बीतने के साथ अधिक निश्चित शब्दों में व्यक्त किया गया है। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में **भारत संघ बनाम संकलचंद हिम्मतलाल सेठ और एक अन्य के मामले से निपटते हुए, (2)** [2]न्यायालय ने निम्नानुसार माना:—

> "इस अनुच्छेद में मुख्य शब्द परामर्श और स्थानांतरण हैं। शब्दकोश-वार और लोकप्रिय बोलचाल के अनुसार परामर्श क्या है? इसका अर्थ है सलाह लेना, सलाह लेना। एक साथ विचार-विमर्श का एक तत्व भी अवधारणा में पढ़ा जाता है . । 'परामर्श करना' मार्गदर्शन, निर्देशन या प्रामाणिक जानकारी के लिए आवेदन करना है, सलाह लेना है - जैसे कि वकील से परामर्श करना; एक साथ किसी बात पर चर्चा करना; जानबूझकर (हेवी बनाम मेट्रोपॉलिटन लाइफ इंक कंपनी)। "परामर्श" शब्द का अर्थ है दूसरे की राय या सलाह लेना; सलाह लेने के लिए; एक साथ विचार-विमर्श करना; प्रदान करने के लिए: सूचना या निर्देश के लिए आवेदन करना। (सी.आई.आर. बनाम जॉन ए. वाथेन डिस्टिलरी कं)। "परामर्श" का अर्थ है दूसरे की राय या सलाह लेना: सलाह लेना: एक साथ विचार-विमर्श करना: प्रदान करना: विचार-विमर्श करना: चर्चा करना: लाने के लिए सलाह लेना; तैयार करें: पश्चाताप: सलाह मांगना: जानकारी प्राप्त करना: जानकारी या निर्देश के लिए आवेदन करना: संदर्भित करना। टेप्लिट्स्की बनाम सिटी ऑफ न्यूयॉर्क स्टराउंड ्स लॉ लेक्सिकॉन परामर्श को इस प्रकार परिभाषित करता है:
>
> > हम एक चिकित्सक या वकील, एक इंजीनियर या एक वास्तुकार से परामर्श करते हैं, और इस प्रकार हमारा मतलब आकस्मिक नहीं बल्कि गंभीर, जानते हुए सूचित सलाह, सक्षम मार्गदर्शन और सुविचारित राय की तलाश करना है। आवश्यक रूप से, परामर्श करने वाले व्यक्ति के कब्जे में सभी सामग्रियों को परामर्शी के समक्ष अनारक्षित रूप से रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, जानकारी प्राप्त करने, अन्य स्टू लेने और प्रभावी और सार्थक सलाह देने के लिए तैयार होने का एक उचित अवसर उसे दिया जाना

[2] (1977) 4 एस.सी.सी.

चाहिए। बदले में, सलाहकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि विषय गंभीर महत्व का है। प्रभावित पक्ष उच्च स्तरीय पदाधिकारी हैं और गलत निर्णय का प्रभाव दुखद हो सकता है। इसलिए, यह इस प्रकार है कि राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश को सभी सामग्री के बारे में सूचित करना चाहिए। उसके पास है और वह जो पाठ्यक्रम प्रस्तावित करता है। बदले में, मुख्य न्यायाधीश को जिम्मेदार चैनलों के माध्यम से या सीधे आवश्यक जानकारी एकत्र करनी चाहिए, आवश्यक डेटा से खुद को परिचित करना चाहिए, अपने पास मौजूद जानकारी पर विचार-विमर्श करना चाहिए और न्याय प्रशासन के हित में आगे बढ़ना चाहिए ताकि राष्ट्रपति को कार्रवाई का ऐसा परामर्श दिया जा सके जो उन्हें लगता है कि सार्वजनिक हित, विशेष रूप से न्याय प्रणाली के कारण को आगे बढ़ाएगा। हालांकि, परामर्श सहमति से अलग है। वे चर्चा कर सकते हैं लेकिन असहमत हो सकते हैं: वे प्रदान कर सकते हैं लेकिन सहमत नहीं हो सकते हैं। और किसी भी मामले में इसमें शामिल न्यायाधीश की सहमति विशेष रूप से अनुच्छेद 222 की सीमा के भीतर एक कारक नहीं है।

(13) **चंद्रमौलेश्वर प्रसाद बनाम पटना उच्च न्यायालय और अन्य** के मामले में, (3)[3], यह निम्नानुसार माना गया था:—

"सवाल उठता है कि क्या 17 अक्टूबर, 1968 की अधिसूचना जारी करने में सरकार की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुपालन में थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिला न्यायाधीश के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति राज्यपाल के पास है, लेकिन वह अपनी पहल पर नियुक्ति नहीं कर सकता है और उच्च न्यायालय के परामर्श से ऐसा करना चाहिए। लेख का अंतर्निहित विचार यह है कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के साथ विचार-विमर्श के बाद अपना मन बनाना चाहिए।

"...राज्यपाल अनुच्छेद 233 के तहत अपने कार्य का निर्वहन नहीं कर सकता है यदि वह इस संबंध में उच्च न्यायालय के विचारों को सुनिश्चित किए बिना किसी व्यक्ति की नियुक्ति करता है। बिहार राज्य की ओर से जोरदार तर्क दिया गया था कि न्यायालय के समक्ष मौजूद सामग्री से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि 17 अक्टूबर, 1968 की अधिसूचना जारी करने से पहले उच्च न्यायालय के साथ परामर्श किया गया था। यह कहा गया था कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में सरकार को अपना दृष्टिकोण दिया था, सरकार को सभी

[3] 1969 (3) एससीसी 56

> तथ्यों के साथ तैनात किया गया था और अनुच्छेद 233 के उद्देश्य के लिए पर्याप्त परामर्श था। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। परामर्श या विचार-विमर्श पार्टियों के समक्ष पूर्ण या प्रभावी नहीं है ताकि वे अपने संबंधित दृष्टिकोण को दूसरे या दूसरों को बता सकें और अपने विचारों के सापेक्ष गुणों पर चर्चा और जांच कर सकें। यदि एक पक्ष दूसरे पक्ष को एक प्रस्ताव देता है, जिसके दिमाग में एक जवाबी प्रस्ताव है, जो प्रस्तावक को सूचित नहीं किया गया है, तो बिना कुछ और के जवाबी प्रस्ताव को प्रभावी करने का निर्देश परामर्श के बाद जारी नहीं किया जा सकता है। हमारी राय में, 17 अक्टूबर, 1968 की अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुपालन में नहीं थी। परामर्श के अभाव में 17 अक्टूबर, 1968 की अधिसूचना की वैधता को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

(14) **एसपी संपत कुमार बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में, (4),** [4] सुप्रीम कोर्ट केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति की जांच करने से संबंधित था। कार्यपालिका के प्रभाव ो से न्यायपालिका की पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक अधिदेश पर जोर देते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन नियुक्तियों को करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीके का सुझाव दिया और उक्त प्रावधानों में विचार किए गए परामर्श को प्रभावी परिणाम दिया।

> उन्होंने कहा, 'संविधान निर्माताओं ने कार्यपालिका के दबाव या प्रभाव से न्यायपालिका की पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए चिंताजनक प्रावधान किए हैं। जाहिर है, इसलिए, यदि उच्च न्यायालय के प्रतिस्थापन में प्रशासनिक न्यायाधिकरण बनाया जाता है और अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को छीन लिया जाता है और प्रशासनिक न्यायाधिकरण में निहित किया जाता है, तो अध्यक्ष को कार्यकारी दबाव के प्रभाव की संभावना से समान स्वतंत्रता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उपाध्यक्ष और सदस्य। अन्यथा प्रशासनिक अधिकरण उच्च न्यायालय के लिए समान रूप से प्रभावी और प्रभावी विकल्प नहीं रह जाएगा और लागू किए गए अधिनियम के प्रावधान अवैध हो जाएंगे। अत, मेरा विचार है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्षों और प्रशासनिक सदस्यों की नियुक्ति संबंधित सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही की जानी चाहिए और ऐसा परामर्श सार्थक और प्रभावी होना चाहिए और सामान्यत: भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश को तब तक

---

[4] 1987 (1) एससीसी 124

स्वीकार किया जाना चाहिए जब तक कि ठोस कारण न हों। किस स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश को कारणों का खुलासा किया जाना चाहिए और ऐसे कारणों के लिए उनकी प्रतिक्रिया आमंत्रित की जानी चाहिए। एक अन्य विकल्प भी है जिसे सरकार द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए अपनाया जा सकता है। उपाध्यक्ष और सदस्य और वह भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति का गठन कर सकते हैं। नियुक्ति के ये दोनों तरीके प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के संचालन के लिए उचित और सक्षम व्यक्तियों का चयन सुनिश्चित करेंगे और इसे प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे जो प्रशासनिक ट्रिब्यूनल का संचालन करने वालों की क्षमता, निष्पक्षता और निष्पक्षता के संबंध में जनता के दिमाग में विश्वास को प्रेरित करेगा, यदि नियुक्ति के इन दो तरीकों में से कोई एक अपनाया जाता है, यह आक्षेपित अधिनियम को अमान्य होने से बचाएगा। अन्यथा, यह अनुच्छेद 323-ए के तहत संसद को प्रदत्त शक्ति के दायरे से बाहर होगा। तथापि, मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि यह निर्णय केवल भावी प्रभाव से ही कार्य करेगा और प्रशासनिक अधिकरण में पहले से की गई नियुक्तियों को अमान्य नहीं करेगा। लेकिन अगर उपाध्यक्षों या प्रशासनिक सदस्यों की कोई नियुक्ति इसके बाद की जानी है, तो यह सरकार द्वारा नियुक्ति के उपरोक्त दो तरीकों में से किसी एक के अनुसार की जाएगी।

(15) **हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंद्र मारवाह**[5] **(5) और जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम एआर जक्की के मामले में, (6)**[6] माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रभावी परामर्श की आवश्यकता पर बल दिया और न्यायिक सेवाओं के संबंध में उच्च न्यायालय के नियंत्रण और अधिकार के दायरे पर भी जोर दिया। इस न्यायालय की खंडपीठ ने **राजिंदर पाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य** [7]के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के वर्गीकरण पर चर्चा करने के बाद (7) निम्नानुसार निर्णय दिया:—

> "उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को एक विशेषज्ञ निकाय की तुलना में भी उच्च स्तर पर रखा जाना चाहिए क्योंकि एक ओर, उच्च न्यायालय नियमों, विनियमों के निर्माण और उम्मीदवारों के चयन में प्रभावी ढंग से भाग लेता है, जबकि दूसरी ओर, यह राज्य में न्यायिक सेवाओं के कामकाज की जमीनी स्तर से लेकर राज्य में

---

[5] 1973 (2) एसएलआर 137

[6] 1992 (3) एसएलआर 3

[7] 2003 (6) एसएलआर 676

निर्णयों की सर्वोच्च अंतिमता तक निगरानी करता है। उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण राज्य में न्यायिक प्रशासन की व्यावहारिक वास्तविकताओं पर आधारित सोच की वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया पर आधारित है। संवैधानिक जनादेश की उचित उपलब्धियों और कार्यान्वयन के लिए संबंधित घटकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रावधानों, और कार्यप्रणाली की योजना और सेवा में उच्च मानक के इष्टतम रखरखाव को प्राप्त करने और इष्टतम रखरखाव के लिए इस तरह से बनाए गए नियमों का प्रवर्तन है, जो जमीनी स्तर पर न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।

" .....हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण पर सरकार और आयोग द्वारा निष्पक्ष रूप से और वरीयता के साथ विचार किए जाने की आवश्यकता है। सेवा में उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए उच्च प्रतिशत का नुस्खा किसी भी तरह से नियुक्ति के लिए समानता या समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। बाल मुकंद साह (सुप्रा) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम उच्च न्यायालय की भूमिका और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव को अपनाने के लिए राज्य की ओर से आवश्यकता पर पुन जोर दें। उद्देश्यपूर्ण परामर्श अनिवार्य रूप से परिणाम उन्मुख, उद्देश्य प्राप्त करने वाला होना चाहिए और इसके निर्णय और निष्कर्ष को अत्यंत अभियान के साथ प्रभावी किया जाना चाहिए। यह अकेले न्याय के उचित प्रशासन के हित में होगा।

(16) अधिनियम की धारा 16 (1) (ए) के प्रावधान **आशीष हांडा अधिवक्ता बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश और अन्य** (8)[8]के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष निर्धारण का विषय थे। लॉर्डशिप ने अधिनियम की योजना पर विचार किया और स्पष्ट शब्दों में यह विचार व्यक्त किया कि राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही की जानी चाहिए और वास्तव में प्रस्ताव मुख्य न्यायाधीश से शुरू किया जाना चाहिए। मामले को अस्पष्टता से परे रखने के लिए, शीर्ष न्यायालय के प्रासंगिक निष्कर्षों को निम्नानुसार संदर्भित करना उचित होगा:

"ऐसा इसलिए है क्योंकि इन एजेंसियों का कार्य मुख्य रूप से उपभोक्ता विवादों का निर्णय है और इसलिए, न्यायिक शाखा के

[8] एआईआर 1996 एससी 1308

एक व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद के लिए उपयुक्त माना जाता है। राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के कार्यालय के परामर्श के बाद ही की जानी है। मुख्य न्यायाधीश के साथ पूर्व परामर्श की आवश्यकता वाले इस तरह के प्रावधान स्पष्ट रूप से इस कारण से है कि वह आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की उपयुक्तता के बारे में जानने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। राज्य आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए धारा 16 (1) (ए) में और राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए धारा 20 (1) (ए) में प्रावधान अनिवार्य हैं और उन्हें समान रूप से माना जाना चाहिए। धारा 16 (1) (ए) और धारा 20 (1) (ए) में परंतुक का निर्माण भाषा की पहचान के कारण समान होना चाहिए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद और भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद अभिव्यक्ति को उसी तरह से माना जाना चाहिए जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद अभिव्यक्ति। भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट -ऑन - रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1993)4 एससीसी 441: (1993 एआईआर एससीडब्ल्यू 4101) में बनाया था। तदनुसार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राय और धारा 16 (1) (ए) में परंतुक के अनुसार उनके साथ परामर्श की आवश्यकता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान दर्जा होना चाहिए: और राज्य आयोग के अध्यक्ष के कार्यालय में नियुक्ति की प्रक्रिया भी समान होनी चाहिए। न्यायाधीश-II मामले (सुप्रा) में बहुमत की राय में संक्षेप में जो कुछ भी कहा गया है, उसे फिर से बताना अनावश्यक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने और इस तरह की नियुक्ति के लिए कार्यपालिका पर निर्भर किसी मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की किसी भी संभावना से बचने के लिए यह आवश्यक है। हमारा ध्यान सरवन सिंह लांबा बनाम भारत संघ, (1955) 4 एससीसी 546: (1995 एआईआर एससीडब्ल्यू 2706) में कुछ टिप्पणियों की ओर दिलाया गया था, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण में नियुक्ति के लिए नाम कार्यपालिका द्वारा भी सुझाया जा सकता है, जिसका प्रस्ताव शुरू करने का प्रभाव हो सकता है। उस मामले के तथ्यों में, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता का पर्याप्त अनुपालन साबित हुआ

और इसलिए, नियुक्तियों को बरकरार रखा गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 16 (1) (ए) और धारा 20 (1) (ए) के परंतुक में मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श की आवश्यकता अनुच्छेद 217 के समान है, इसलिए न्यायाधीशों के मामले में बहुमत की राय में प्रतिपादित सिद्धांत लागू होने चाहिए, जैसा कि पहले बताया गया है, यहां तक कि प्रस्ताव शुरू करने के लिए भी। कार्यपालिका से अपेक्षा की जाती है कि जब प्रस्ताव को शुरू करने के लिए कदम उठाने के लिए नियुक्ति की जानी हो तो वह मुख्य न्यायाधीश से संपर्क करे और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया समान होनी चाहिए। इससे की गई नियुक्ति को अधिक विश्वसनीयता मिलेगी।

4. अब प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान मामले में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 16(1)(क) के परंतुक का समुचित अनुपालन किया गया है? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार श्री बीएल गुलाटी के 9 जुलाई, 1994 के हलफनामे में हरियाणा राज्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री एमआर अग्निहोत्री की नियुक्ति में अपनाई गई प्रक्रिया का उल्लेख है। यह ज्ञात है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने उस उच्च न्यायालय के कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नामों पर विचार किया और अंततः राज्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में श्री एमआर अग्निहोत्री की नियुक्ति के लिए अपनी सहमति दी, जिसे रजिस्ट्रार द्वारा 10 जून को हरियाणा सरकार को सूचित किया गया था। 1994 में श्री एम. आर. अग्निहोत्री की नियुक्ति की गई। वर्तमान मामले के तथ्यों में, हम पाते हैं कि अधिनियम की धारा 16 (1) (ए) के परंतुक का पर्याप्त अनुपालन किया गया था और श्री एमआर अग्निहोत्री की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की गई थी। तथापि, हम यह भी जोड़ सकते हैं कि जैसा कि जज-II मामले में दर्शाया गया है, अपनाने के लिए उपयुक्त तरीका यह है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रस्ताव को आरंभ करें और नियुक्ति के लिए उनके द्वारा अनुमोदित उसी का उल्लेख करें बजाय इसके कि मुख्य न्यायाधीश केवल राज्य सरकार द्वारा सुझाए गए नाम का अनुमोदन करें। रजिस्ट्रार के हलफनामे से ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार को पद को भरने के लिए प्रस्ताव शुरू करने से संबंधित उचित प्रक्रिया का संकेत दिया था और उन्होंने कई नामों पर विचार करने के बाद ही श्रीक एमआर अग्निहोत्री की नियुक्ति को अपनी मंजूरी दी थी, जिसमें क्रीक एमआर अग्निहोत्री भी शामिल थे। इसलिए, वर्तमान मामले में की गई नियुक्ति किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करती है।

5. नतीजतन, स्थानांतरित मामले को खारिज कर दिया जाता है।

17. अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं और उच्च न्यायालय के नियंत्रण और राज्य के मामलों में परामर्श के प्रभाव से संबंधित एक हालिया फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने **गौहाटी उच्च न्यायालय बनाम कुलधर फुकन**[9] के मामले में, (9) यह विचार व्यक्त किया कि परामर्श प्रभावी होना चाहिए और इसकी सामग्री में पारस्परिकता और उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के लॉर्डशिप के संबंध निम्नानुसार हैं -

> "....केवल इसलिए कि राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचनाओं की एक प्रति उच्च न्यायालय को भेज दी है, परामर्श की आवश्यकता को संतुष्ट नहीं कहा जा सकता है। न तो इसे राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था और न ही उच्च न्यायालय ने अपनी शक्ति, विशेषाधिकार का उपयोग या निर्वहन किया था। और परामर्श का दायित्व। परामर्श जैसी अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकता का पालन करने में विफलता के कारण होने वाली अयोग्यता को एक या दोनों पदाधिकारियों की ओर से सरासर निष्क्रियता से ठीक नहीं किया जा सकता है, जिनके बीच आवश्यकता को पूरा किया जाना था या केवल समय की समाप्ति से।
>
> "....उच्च न्यायालय की खंडपीठ अनावश्यक रूप से इस तथ्य से प्रभावित हुई कि उच्च न्यायालय ने 17 सितंबर, 1996 को अधिसूचना को वापस लेने के पीछे के कारण की अनदेखी करते हुए 10 अप्रैल, 1955 की अपनी अधिसूचना को वापस ले लिया था। प्रतिवादी नंबर 1 को न्यायिक अधिकारी के रूप में तैनात करने वाली अधिसूचना को वापस लेना पड़ा क्योंकि इसे लागू नहीं किया गया था और इसे वापस लेने की आवश्यकता थी ताकि न्यायिक कार्यालय को दायर करने वाली एक और अधिसूचना जारी की जा सके। इसलिए डिवीजन बेंच ने एक राय बनाते समय संवैधानिक प्रावधान के प्रभाव को नजरअंदाज कर दिया कि न्यायिक सेवा में प्रतिवादी नंबर 1 का ग्रहणाधिकार स्वचालित रूप से समाप्त हो गया था क्योंकि प्रतिवादी नंबर 1 की कानूनी सेवा में नियुक्ति, जबकि वह न्यायिक सेवा का सदस्य था, उच्च न्यायालय के परामर्श के बिना की गई थी और इसलिए अमान्य थी। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा कानूनी प्रक्रिया में ग्रहणाधिकार प्राप्त करने और न्यायिक सेवा में ग्रहणाधिकार को समाप्त करने का सवाल ही नहीं उठता। उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इसे रद्द किया जा सकता है।

---

[9] 2002 (2) एससीटी 768

राष्ट्रीय उपभोक्ता जागरूकता समूह (रजि.) बनाम भारत संघ और अन्य (स्वतंत्र कुमार, जे)

(18) हाल ही में दिए गए एक अन्य फैसले में जिसका शीर्षक है **भारत संघ और दूसरा बनाम एसबी वोहरा और अन्य, (10)**[10] नियम बनाने के लिए मुख्य न्यायाधीश की शक्ति से निपटते हुए और सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 229 (2) के तहत मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर कार्रवाई करने से इनकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के लॉर्डशिप ने उस प्रधानता का संकेत दिया जिसे मुख्य न्यायाधीश की राय को दिया जाना चाहिए और उन्होंने निम्नानुसार रखा:—

> "इस न्यायालय के निर्णय, जैसा कि पहले चर्चा की गई है, स्पष्ट शब्दों में यह सुझाव नहीं देते हैं कि यह भारत संघ या संबंधित राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है कि वह सामान्य रूप से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जैसे उच्च पद के धारक द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार करे और केवल असाधारण मामलों में उसकी सिफारिश से भिन्न हो। इस तरह के उच्च पद के धारक की राय से अलग होने का कारण ठोस और पर्याप्त होना चाहिए। यहां तक कि इस तरह के मतभेद के मामले में, अधिकारियों को आपस में चर्चा करनी चाहिए और मतभेदों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। दुर्भाग्य से अपीलकर्ता ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया।
>
> "इस न्यायालय की उपरोक्त आधिकारिक घोषणाओं के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों को आमतौर पर राज्य द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और उन्हें मजबूत और पर्याप्त कारणों से अस्वीकार किया जाना चाहिए। इस मामले में अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय द्वारा की गई सिफारिशों पर भी खुद को संबोधित किया। वे इस मामले को हल्के में नहीं ले सकते थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्य न्यायाधीश जैसे उच्च पदाधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया और निजी प्रतिवादियों को रिट याचिका दायर करनी पड़ी। उच्च न्यायालय के वेतनमान में संशोधन के निर्धारण के संबंध में प्रश्न उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विशेष अधिकार क्षेत्र में है, अनुमोदन के अधीन, राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह अच्छे और ठोस कारणों के अलावा समान सिफारिशों को स्वीकार करे।

(19) उपरोक्त निर्णयों में उच्चतम न्यायालय के सुसंगत दृष्टिकोण के आलोक में, अब हम राज्य आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में धारा 16 (1) (ए) के प्रावधानों की व्याख्या पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, जो वर्तमान रिट याचिकाओं का विषय है।

---

[10] JT 2004 (1) SC 38

(20) जहां तक अधिनियम की धारा 16(1)(क) के उपबंधों का संबंध है, संविधि में बार-बार परिवर्तन किए जाने के बावजूद विधायिका ने अपने विवेक से बिना किसी परिवर्तन के अपनी भाषा को बनाए रखा है। इस प्रावधान के दायरे और अर्थ और परामर्श के प्रभाव पर देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित निर्णयों में चर्चा की गई है। यह स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि परामर्श स्पष्ट रूप से उद्देश्यपूर्ण होगा और आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति पर विचार करते समय मुख्य न्यायाधीश के विचार को अनिवार्य रूप से प्राथमिकता दी जानी चाहिए। परामर्श में राज्य पर यह दायित्व डाला गया है कि वह मुख्य न्यायाधीश की सलाह ले और उसे उचित वरीयता के साथ स्वीकार करे, जब तक कि राज्य के पास सुझाए गए नाम पर पुनर्विचार के लिए मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करने का बाध्यकारी कारण न हो। राज्य उस घटना में अपने अधिकार की सीमाओं को पार नहीं करेगा, भले ही वह आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए किसी अन्य नाम का सुझाव दे। यदि मुख्य न्यायाधीश के अंत में इस पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाती है, तो यह अधिनियम के उद्देश्य के साथ-साथ निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से पूरा करेगा। वरीयता एक मूल्यवान शब्द है और इसे निष्पक्ष रूप से समझा जाना चाहिए। इस तरह के निर्माण और दृष्टिकोण को इस कारक से और अधिक प्रमाणित किया जाएगा कि मुख्य न्यायाधीश एक संवैधानिक पदाधिकारी हैं और उनके पास जांच, जांच और निष्पक्ष राय देने की विशेषज्ञता है, जो न्याय के प्रशासन के कारण को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। राज्य आयोगों को अधिनियम के प्रावधानों के तहत न्यायिक कार्य करना है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के अधीन है। **एल. चन्द्र कुमार बनाम भारत संघ और अन्य**[11] के मामले में सात माननीय न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि उच्च न्यायालय में निहित शक्ति अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अपने अधीक्षण का प्रयोग करने की भी संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। अधिकरणों से अनुपूरक कार्यों का निर्वहन करने की अपेक्षा की जाती है और उनके निर्णय और आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे, जैसा भी मामला हो। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में निहित विधायी कार्रवाई पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की एक अभिन्न और आवश्यक विशेषता है, जो इसकी मूल संरचना का हिस्सा है। आमतौर पर, इसलिए, कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने के लिए उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को कभी भी बाहर नहीं किया जा सकता है।

(21) फिर भी **सरवन सिंह लांबा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य**[12] के मामले में, सुप्रीम कोर्ट के लॉर्डशिप ने आगे कहा कि अंतिम निर्णय समिति की

[11] AIR 1997 SC 1125
[12] (1995) 4 SCC 546

सिफारिश पर मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिया जाएगा और कानून का इस हद तक विस्तार किया गया था कि आम तौर पर राज्य और उसकी एजेंसियों द्वारा एक अस्पष्ट आदेश का पालन और पालन करने की उम्मीद की जाती है। यह केवल सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं है, बल्कि निश्चित रूप से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य प्रशासन के बीच "परामर्श" अभिव्यक्ति के दायरे और अर्थ को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों का पालन करना उन सभी घटकों का दायित्व है जिन्हें आयोग के अध्यक्ष सहित उच्च पदों की नियुक्ति में निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेना है। किसी भी अनिश्चित शब्दों में यह नहीं कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश की राय का वरीयता के साथ सम्मान किया जाना चाहिए और सामान्य रूप से बहुत मजबूत और ठोस कारणों के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि राज्य प्रशासन इस अपवाद का सहारा लेता है, तो उसे मुख्य न्यायाधीश से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हुए ठोस और वैध कारण देने चाहिए। पारस्परिक विचार-विमर्श या अन्यथा और राज्य द्वारा बताए गए कारणों पर विचार करने पर, यदि मुख्य न्यायाधीश सिफारिश को दोहराते हैं, तो राज्य सामान्य रूप से ऐसी राय से बाध्य होगा। इस तरह का दृष्टिकोण अपनाने के दो कारण हैं। सबसे पहले, ऐसे वैधानिक पदों पर नियुक्ति को अनावश्यक रूप से विलंबित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अनिश्चितकालीन देरी का व्यापक जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है क्योंकि इससे आयोग द्वारा मामलों के निपटारे में देरी होगी। यह आयोग के न्यायिक और प्रशासनिक कामकाज को प्रभावित करने के लिए बाध्य है। दूसरे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपनी विशेषज्ञता और न्याय के व्यापक प्रशासनिक नियंत्रण के कारण अधिक उपयुक्त उम्मीदवार की सिफारिश करने के लिए राज्य प्रशासन की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं।

(22) विभिन्न विचारों की संभावना को मिटाया नहीं जा सकता है, खासकर जब यह अच्छे और वैध कारणों से हो। विचारों में मतभेद, यदि कोई हो, को आपसी चर्चा, उद्देश्यपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण से हल किया जाना चाहिए। लेकिन, किसी भी मामले में, राय की इस डेड-लॉक अंतिमता को तोड़ने के लिए संकेत दिया जाना चाहिए। हमारे विचार से आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में अंतिम निर्णय मुख्य न्यायाधीश के पास होना चाहिए।

(23) बिना किसी ठोस और ठोस कारण के मुख्य न्यायाधीश की राय को नीचा दिखाना एक उचित अभ्यास नहीं होगा और इसके परिणामस्वरूप न्यायपालिका की गरिमा भी कम होगी और पूरी संभावना है कि न्याय के उचित प्रशासन में बाधा उत्पन्न होगी।

(24) सर्वोच्च न्यायालय की घोषणाओं में, मुख्य रूप से भारत के संविधान का अनुच्छेद 217 व्याख्या का विषय रहा है, जहां उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की

नियुक्ति "भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद" की जानी है। इस अभिव्यक्ति की व्याख्या करते समय न्यायालयों ने मुख्य न्यायाधीश की राय को वरीयता देने की आवश्यकता पर जोर दिया है और यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पीछे के संदर्भ में सिफारिश दोहराई जाती है, तो ऐसी सिफारिश एक राज्य के लिए बाध्यकारी होगी। अनुच्छेद 229 (2) के तहत वेतन, भत्ते, छुट्टी या पेंशन के संबंध में नियम मुख्य न्यायाधीश या राज्य के अनुमोदन से इस संबंध में अधिकृत अधिकारी द्वारा तैयार किए जाएंगे। यह माना गया है कि राज्य अपनी बात रख सकता है यदि उसे मुख्य न्यायाधीश के विचार के लिए अपने कारणों के साथ अनुदान या अनुमोदन के लिए कोई आपत्ति है और यदि विचार दोहराया जाता है, तो राज्य से उम्मीद की जाती है कि वह मुख्य न्यायाधीश के दृष्टिकोण को उचित वरीयता के साथ स्वीकार करेगा। विधायिका ने अपने विवेक से धारा 16 (1) (ए) के परंतुक को दृढ़ता से और मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श की आवश्यकता पर अधिक जोर दिया है। संविधान के अनुच्छेद 227 की भाषा से कुछ अलग होने पर, विधायिका ने "उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बिना " शब्दों का उपयोग किया है। भाषा का उद्देश्य न केवल मुख्य न्यायाधीश के दृष्टिकोण को अधिक महत्व और जोर देना प्रतीत होता है, बल्कि इस तरह के परामर्श के अभाव में नियुक्ति पर भी रोक लगाना है। **सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ**[13], (13) के मामले में, सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्डशिप ने कहा कि अनुच्छेद 124 (2) और 217 (1) के प्रयोजनों के लिए, मुख्य न्यायाधीश की राय को सभी नियुक्तियों के मामले में प्रधानता है और इन प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति द्वारा कोई नियुक्ति तब तक नहीं की जा सकती है जब तक कि यह मुख्य न्यायाधीश की अंतिम राय के अनुरूप न हो। भारत, फैसले में बताए गए तरीके से गठित हुआ। माननीय उच्चतम न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने राष्ट्रपति संदर्भ (14)[14] में इस सिद्धांत को दोहराया कि उस निर्णय में दर्शाए गए तरीके से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित राय को नियुक्ति के मामलों में प्रमुखता दी जानी चाहिए। एक बार परामर्श प्रक्रिया के मानदंडों और आवश्यकताओं के अनुरूप सिफारिशें किए जाने के बाद, राय, इस प्रकार, बाध्यकारी होगी।

(25) अंतिमता विचारों के टकराव से आ सकती है। दूसरों की राय पर उचित विचार किया जाना चाहिए। आपसी विचार-विमर्श और स्वस्थ तर्क एक वस्तुनिष्ठ निर्णय की नींव होते हैं, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ठोस और उचित कारणों से एक और दृष्टिकोण उभरना चाहिए, जो वर्तमान मामले में, न्याय प्रशासन के एक प्रशंसनीय उद्देश्य से संबंधित है। राज्य को धारा 16 (1) (ए) के दायरे में अपने विचार रखने और मामले

---

[13] 1993 (4) एससीसी 441

[14] एआईआर 1999 एससी पेज 1

को पुनर्विचार के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास भेजने का अधिकार है। एक बार मुख्य न्यायाधीश द्वारा कारणों पर विचार किया जाता है और सिफारिश ो को दोहराया जाता है, तो राज्य मुख्य न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किए गए विचार को किसी भी दृढ़ता से मुक्त करने के लिए बाध्य है। राज्य आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया का यही आधार है। हमारे विचार में इस तरह की व्याख्या अकेले कानून के प्रावधानों के कारण को आगे बढ़ाएगी और न्याय प्रशासन से संबंधित संस्थानों की गरिमा और स्वतंत्रता को बनाए रखेगी।

(26) मामले के इस पहलू से निपटने के बाद। इस स्तर पर ही यह ध्यान देना उचित होगा कि इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने वर्तमान रिट याचिका पर विचार करते हुए,-- अपने दिनांक 17 नवम्बर, 2003 के आदेश के माध्यम से प्रतिवादियों को न्यायालय में रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। जो रिकॉर्ड पहले पेश किए गए थे, उन्हें भी सुनवाई के दौरान हमारे सामने पेश किया गया है। जैसा कि हम मुख्य रूप से इन दो याचिकाओं में उठने वाले कानून के प्रश्नों से निपट रहे हैं, हमारा the विचार है कि चूंकि यह मामला प्रभावी रूप से विचाराधीन है और पहले ही काफी अग्रिम चरण में आगे बढ़ चुका है, इसलिए न्याय और औचित्य के हित की मांग होगी कि हम तथ्यात्मक मैट्रिक्स और योग्यता या स्थिति के अन्यथा में प्रवेश न करें।हमारे समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकट होने वाले मामले। यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि मुख्य न्यायाधीश (कॉलेजियम के अन्य माननीय न्यायाधीशों के साथ) ने मुख्यमंत्री द्वारा बताए गए कारणों पर उचित विचार करने के बाद अपनी राय को फिर से दोहराया है। इस निर्णय के आलोक में इस मामले पर अंतिम निर्णय लेना संबंधित प्राधिकारियों का कार्य होगा।

राज्य आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित सांविधिक योजना पर धारा 16(1-क) के उपबंधों का प्रभाव

(27) इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को अक्सर विधायी संशोधन के अधीन किया गया है। ऐसे संशोधनों के बावजूद धारा 16 (1) (ए) के प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 1993 के संशोधन अधिनियम संख्या 50 के तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की घोषणाओं के बाद,--विधायिका ने अधिनियम की धारा 16 (1) (ए) के परंतुक को पेश किया था। उस समय धारा 16 की उप-धारा (1) के खंड (बी) में आयोग में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नामों की सिफारिश करने के लिए एक समिति के गठन का भी प्रावधान था, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना था।

(28) उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 का 62) द्वारा अधिनियम की धारा 16 में पर्याप्त संशोधन, परिवर्धन और प्रतिस्थापन पेश किए गए थे। धारा 16 (1) (बी) के तहत सदस्यों की योग्यता बताई गई थी, सदस्य के

रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्यता को पेश करने वाला एक और परंतुक बताया गया था। परंतुक के स्थान पर, धारा 16 (1) (बी) को धारा 16 (1 ए) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इसके अलावा, आयोग के अध्यक्ष के अनुपस्थिति या अन्य कारणों से भाग लेने में सक्षम नहीं होने की स्थिति में चयन समिति के अध्यक्ष की रिक्ति की आपूर्ति करने के उद्देश्य से एक परंतुक भी पेश किया गया था। अन्य संशोधनों के अलावा, एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया जिसमें राज्य आयोग के वर्तमान अध्यक्ष को क़ानून के प्रावधानों के अनुसार पुन: नियुक्ति के लिए पात्र बनाया गया। इस सब के बावजूद, सबसे ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि धारा 16 (1) (ए) के प्रावधान अपरिवर्तित और असंशोधित रहे। जैसा कि हमने पहले ही देखा है कि धारा 16 अपने आप में एक पूर्ण संहिता है। यह राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पद पर नियुक्ति के विचार के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है। विशेष रूप से राज्य आयोग के अध्यक्ष की व्यवस्था से संबंधित प्रावधान मुख्य रूप से धारा 16 (1) (ए) में निहित हैं। धारा 16 (1-ए) को शुरू करने का उद्देश्य क्या था और क्या विधायिका ने अपने विवेक से धारा 16 (1) (ए) के प्रावधानों या उसमें निर्धारित प्रक्रिया की भावना में हस्तक्षेप करने का इरादा किया था, यह एक विवादास्पद प्रश्न है जिस पर न्यायालय द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है।

(29) उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1993 के माध्यम से, विधायिका ने धारा 16 (1) (ए) के परंतुक में संशोधन किया था, साथ ही अधिनियम की धारा 16 (1) (बी) में एक नया परंतुक जोड़ा था। इसके बाद अधिनियम की धारा 16 (1) (बी) के मौजूदा परंतुक को हटा दिया गया और धारा 16 (1) (बी), 16 (1-ए), 16 (1-बाई, 16 (2) और 16 (3) के संदर्भ में कुछ संशोधित प्रावधानों को जोड़ा गया, ये प्रावधान नियम और शर्तों से संबंधित हैं, आयोग के सदस्यों के पद पर नियुक्ति के लिए पात्रता आयोग के अध्यक्ष की कुछ शक्तियों का भी उल्लेख करती है। अवधि। हालांकि, धारा 16 (1) (ए) के प्रावधानों के साथ-साथ इसके प्रावधान बरकरार और अपरिवर्तित रहे। उस परंतुक के तहत, खंड (1) (बी) के तहत नियुक्तियां राज्य सरकार द्वारा चयन समिति की सिफारिशों पर की जानी थीं, जिसके सदस्य राज्य आयोग के अध्यक्ष, कानून विभाग के सचिव, राज्य के उपभोक्ता मामलों से निपटने वाले विभाग के प्रभारी सचिव थे। धारा 16 (1-ए) को शुरू किया गया था कि उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक नियुक्ति एक ही चयन समिति द्वारा समान संविधान के साथ की जाएगी। ये संशोधित प्रावधान मुख्य रूप से आयोग के सदस्य की नियुक्ति से संबंधित थे और प्रावधान किया गया था कि राज्य आयोग के अध्यक्ष को पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र बनाया गया था और उनकी अनुपस्थिति में मुख्य न्यायाधीश को चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए वर्तमान न्यायाधीश को नामित करना आवश्यक था। राज्य सरकार को राज्य आयोग के अध्यक्ष की सिफारिश पर पूर्णकालिक सदस्यों की भी नियुक्ति करनी थी। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 16 (1-ए), 16 (1) (बी), 16 (2) और 16 (3) के प्रावधान आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की विधि और तरीके के साथ-

साथ आयोग के अध्यक्ष में निहित अधिकार और शक्ति से काफी हद तक संबंधित हैं। दूसरे शब्दों में, इस धारा के विभिन्न खंड आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित नहीं हैं, जो बदले में चयन समिति का अध्यक्ष होता है। हम यह भी देख सकते हैं कि हरियाणा उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1988 इस संबंध में पूरी तरह से चुप हैं। धारा 16 (1-ए) की शुरुआती पंक्तियों में कुछ शब्दों का उपयोग धारा 16 (1) (ए) के प्रावधानों के साथ-साथ धारा 16 (1-ए) के उपखंडों में विचार की गई पूरी विधायी योजना को निराश नहीं करेगा। इस मामले के इस पहलू के लिए अब हमें धारा 16 (1-ए) के संशोधित प्रावधानों को पेश करने की पृष्ठभूमि की जांच करने की आवश्यकता है।

उद्देश्य और कारण:—

(30) एक विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का विवरण, जो अंततः एक क़ानून में अधिनियमित होता है, क़ानून की व्याख्या के लिए प्रत्यक्ष उपदेश नहीं है। **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम उनके कामगार (15)**[15] के मामले में, न्यायालय ने कहा कि उद्देश्यों और कारणों का विवरण स्वीकार्य नहीं है, हालांकि, धारा का अर्थ निकालने के लिए यह उपयोग किए गए वास्तविक शब्दों को बहुत कम नियंत्रित कर सकता है। यह अच्छी तरह से तय है कि संसद में पेश किए जाने पर विधेयक के साथ उद्देश्यों और कारणों के बयान का उपयोग कानून के मूल प्रावधानों के सही अर्थ और प्रभाव को निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता है, लेकिन कानून की पृष्ठभूमि, पूर्ववृत्त और मामलों की स्थिति को समझने के लिए सीमित उद्देश्य के लिए बहुत मदद करता है। बिल के उद्देश्यों और कारणों का संदर्भ, निश्चित रूप से, एक सीमित उद्देश्य के लिए हमेशा किया जा सकता है। यह ऐतिहासिक तथ्यों या आसपास की परिस्थितियों का एक उचित संकेतक या सबूत है जिसने विधायिका को प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन करने के लिए राजी किया।

(31) 2002 का अधिनियम संख्या 62, जिसमें धारा 16 (1-ए) और मौजूदा अधिनियम में कई अन्य संशोधन शामिल थे, में उद्देश्यों और कारणों का एक व्यापक विवरण था जिसे विधेयक की स्वीकृति के लिए संसद में प्रस्तुत किया गया था। यहां तक कि उस अवधि के संबंध में भी विवरण जिसके भीतर शिकायत स्वीकार की जानी चाहिए और नोटिस जारी किया जाना चाहिए और शीघ्र निपटान किया जाना चाहिए। इसमें सुझाए गए संशोधन का मुख्य उद्देश्य अधिनियम के तहत निर्दिष्ट पदानुक्रम में विभिन्न मंचों द्वारा उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटान को प्राप्त करना था। धारा 16 (1) (ए) के प्रावधानों में किसी भी बदलाव को पेश करने के विधायिका के इरादे के संबंध में उद्देश्य और कारण पूरी तरह से मौन हैं, विशेष रूप से किसी भी ऐतिहासिक घटना के संदर्भ में जिसमें धारा 16 (1) (ए) के प्रावधानों के लिए धारा 16 (आई-ए) के संशोधित प्रावधानों को लागू

---

[15] एआईआर 1960 एससी 12

करने की आवश्यकता थी। हम पहले ही देख चुके हैं कि 1993 और 1997 के संशोधित अधिनियमों ने आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए कार्यप्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया है जैसा कि धारा 16 (1) (ए) के प्रावधानों में विचार किया गया है। धारा 16 (1) (ए) के प्रावधान ऐसी नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाले अनुभाग के भीतर एक पूर्ण स्व-निहित धारा को दर्शाते हैं। धारा 16 (1) (बी) के प्रावधान अधिनियम की धारा 16 (1) (ए) के प्रावधानों को शायद ही प्रभावित कर सकते हैं। उन्हें आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए उनका उचित अर्थ दिया जाना चाहिए और अधिनियम की धारा 16 (1) (ए) के प्रावधानों के साथ संघर्ष किए बिना अपने स्वयं के क्षेत्र में काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(32) बहस के दौरान हमारे सामने यह सुझाव नहीं दिया गया था कि उक्त धारा के प्रावधानों ने वांछित परिणाम नहीं दिखाए थे और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के आलोक में उक्त प्रावधानों को संचालित करने में कठिनाई थी। हमारे सामने पेश किए गए रिकॉर्ड आगे यह दर्शाते हैं कि आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति पिछले वर्षों में मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश और दीक्षा पर की गई थी। इस तरह की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया और लागू किया गया और यहां तक कि अगर कुछ संदेह था, तो इसे सौहार्दपूर्ण और निष्पक्ष रूप से हल किया गया था। दूसरे शब्दों में, क़ानून के तहत सभी संबंधित अधिकारियों ने इन प्रावधानों की व्याख्या और समझ को पूर्व-संदर्भित तरीके से समझा और इस प्रकार, एक ऐसी प्रथा की स्थापना की जो कानून के अनुरूप है। कानून द्वारा समर्थित एक अच्छी प्रथा अपने आप में एक मिसाल है और संशोधित प्रावधानों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे इस तरह की प्रथा को नकारा जा सके। दूसरी ओर, न्यायिक निर्णयों ने इसकी प्रयोज्यता की पुष्टि की है। **आशीष ग्रोवर बनाम पंजाब राज्य और अन्य**[16] के मामले में, **पुलिस उपायुक्त और अन्य बनाम मोहम्मद खाजा अली**[17] के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए, निम्नानुसार माना गया:—

> "एक बार जब इस तरह के नियम या निर्देश की व्याख्या की जाती है और उचित अवधि में संबंधित अधिकारियों द्वारा लागू किया जाता है, तो इस तरह के नियम या व्याख्या को अपनाई गई प्रथा के मद्देनजर सही के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जब तक कि इस तरह की प्रथा कुछ संवैधानिक संरक्षण या सार्वजनिक नीति के पूरी तरह से विरोध में न हो।

---

[16] 2001 (1) पीएलआर 10

[17] 2000 (2) एसएलआर 49

(33) अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य किसी दिए गए मामले में कानून के उल्लिखित उद्देश्यों और कारणों से अलग हो सकते हैं। हालांकि, यहां स्थिति ऐसी नहीं है। इन प्रावधानों को देश के सभी राज्यों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। विभिन्न संशोधनकारी अधिनियमों के उद्देश्यों और कारणों के उद्देश्य और कथन में समानता निश्चित रूप से काफी हद तक दर्शाती है कि धारा 16 (1 ए) को पेश करने के लिए कुछ सामान्य नियमों और शर्तों को जोड़ने और धारा 16 (1) (बी) के पहले के परंतुक को अलग-अलग भाषा के साथ प्रस्तुत करने के अलावा कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं था। परिचर परिस्थितियों और धारा की भाषा का संक्षिप्त प्रभाव मौजूदा प्रक्रिया की तुलना में आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता के लिए विधायी इरादे का सुझाव नहीं देता है।

(34) **काका बनाम हसन बानो** [18] के मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने कहा कि किसी अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों को उन कारणों को जानने में सहायता के लिए लाया जा सकता है जिन्होंने विधेयक पारित करने के लिए प्रस्तावक या विधायिका को प्रेरित किया। पीठ ने निम्नानुसार कहा:

> "एक विधेयक में संलग्न उद्देश्यों और कारणों के बयान को एक क़ानून के निर्माण में सहायता के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। किसी अधिनियम या विधेयक के उद्देश्य और कारण केवल इस सीमा तक ही मांग करते हैं कि कौन से कारण प्रस्तावक को सदन में विधेयक पेश करने के लिए प्रेरित करते हैं और वह किस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है। यह आवश्यक नहीं है कि वे हमेशा उस उद्देश्य के अनुरूप होंगे जो विधेयक को कानून में पारित करते समय सदन के बहुमत ने ध्यान में रखा था। यह भी आवश्यक नहीं है कि उद्देश्य और कारण अधिनियम के विशिष्ट या सामान्य प्रावधानों को समझने में मदद करेंगे। श्री न्यायमूर्ति एसके दास ने निम्नलिखित अभिव्यक्ति में इन सिद्धांतों को दोहराया, "उद्देश्य और कारणों का कथन स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, अनुभाग का अर्थ निकालने के लिए यह उपयोग किए गए वास्तविक शब्दों को बहुत कम नियंत्रित कर सकता है। (एआईआर 1960 एससी 12, एआईआर 1971 एससी 1331 और एआईआर 1973 एससी 1293 देखें।

(35) सांविधिक प्रावधानों की व्याख्या के बारे में जानने वालों में से एक बेतुके परिणामों से बचना है। जहां कभी भी दो प्रतिद्वंद्वी व्याख्याएं न्यायालय के समक्ष रखी जाती हैं, एक जो कानून के अनुरूप है और कानून के कारण को आगे बढ़ाती

---

[18] 1998 (1) आरसीआर (आपराधिक) 485

है, उसे अदालत द्वारा दूसरे पर स्वीकार किया जाएगा, जो बेतुके परिणाम या यहां तक कि बेतुकी असुविधा पैदा कर सकता है। बेशक, तर्क असुविधाजनक है जिसे बहुत सावधानी के साथ लागू किया जाना है। कानून के टुकड़े की व्याख्या पर सही ढंग से लागू बेतुकापन का सिद्धांत हास्यास्पद प्रभावों से बचने के लिए अपने दायरे में ले जाएगा। राज्य की ओर से उठाया गया यह तर्क कि धारा 16 (1-ए) धारा 16 (1) (ए) के प्रावधानों को नियंत्रित करेगी और विचाराधीन पद पर चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया चयन समिति द्वारा शुरू और शुरू की जानी है, निराधार है। हो सकता है, प्रावधानों की आकस्मिक दृष्टि से इस तरह की व्याख्या का सुझाव दिया जा सकता है, लेकिन एक बार जब मामले की गहराई से जांच की जाती है और कुछ निष्पक्षता के साथ प्रतिपादित कानून के प्रकाश में, विवाद को खारिज कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, उक्त व्याख्या बेतुके, प्रतिकूल और असुविधाजनक परिणाम उत्पन्न करने के लिए बाध्य है।

(36) यदि आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया धारा 16(1-ए) के तहत यथा विचारित अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों वाली चयन समिति द्वारा शुरू और शुरू की जानी है और यदि उसे संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों के नाम/नामों पर विचार और सिफारिश करनी है, राज्य आयोग के वर्तमान अध्यक्ष सहित, जो धारा 16 (3) के दूसरे परंतुक के तहत विस्तार के लिए विचार किए जाने के हकदार हो सकते हैं, असुविधाजनक और शर्मनाक परिणामों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आयोग के दो सदस्य जो अन्यथा राज्य आयोग के अध्यक्ष की स्थिति में कम हैं, यह भी टिप्पणी कर सकते हैं कि राज्य आयोग के अध्यक्ष पुनः नियुक्ति के योग्य नहीं हैं। परिणाम बेतुका नहीं तो और भी अवांछनीय होगा, जब चयन समिति को उच्च न्यायालय के एक मौजूदा या यहां तक कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नाम पर विचार करना है, जो धारा 16 (1) (ए) के संदर्भ में आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के योग्य होंगे। सिविल प्रशासन के ज्ञात सिद्धांत एक चयन समिति द्वारा पदोन्नति उद्देश्यों के लिए पात्र व्यक्तियों पर विचार करने की अनुमति नहीं देते हैं, जिनके सदस्य प्रशासनिक पदानुक्रम में उस पद से ऊपर नहीं हो सकते हैं जिसके लिए नियुक्तियां की जानी हैं।

(37) उपर्युक्त लेकिन प्रासंगिक का एक और सहायक परिणाम यह है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संरक्षित किया जाना है। यह एक संवैधानिक अधिदेश है कि राज्य के तीन अंग अपने-अपने क्षेत्रों में काम करते हैं और कार्यपालिका या विधायिका को किसी भी तरह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा न्याय के प्रशासन का उल्लंघन या बिगाड़ना नहीं चाहिए। आशीष हांडा (सुप्रा) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने चिंता व्यक्त करते हुए स्वतंत्र न्यायपालिका के रखरखाव की

आवश्यकता और न्यायिक नियुक्तियों में राज्य के अन्य घटकों द्वारा कम से कम हस्तक्षेप पर ध्यान देते हुए निम्नानुसार टिप्पणी की -

> ".। तदनुसार, धारा 16 (1) (ए) में परंतुक के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राय और उनके साथ परामर्श की आवश्यकता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान दर्जा होना चाहिए; और राज्य आयोग के अध्यक्ष के कार्यालय में नियुक्ति की प्रक्रिया भी समान होनी चाहिए। न्यायाधीश-II मामले में बहुमत की राय में संक्षेप में जो कुछ भी कहा गया है, उसे फिर से बताना अनावश्यक है। <u>न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने और इस तरह की नियुक्ति के लिए कार्यपालिका पर निर्भर किसी मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के किसी भी पद को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है।</u> (हमारे द्वारा प्रदान किया गया जोर)।

(38) इस धारणा पर कि एक क़ानून का उद्देश्य न्यायसंगत और उचित होना है, यह आवश्यक है कि संबंधित प्रावधान अपने स्वयं के क्षेत्रों में काम करें। एक व्याख्या जो क़ानून के दो प्रावधानों को प्रभावी बनाते समय संघर्ष पैदा करती है, से बचा जाना चाहिए। धारा 16 (1) (ए) के प्रावधान स्पष्ट हैं और उनकी भाषा में इतने स्पष्ट हैं कि कानून के अनुरूप उनका कार्यान्वयन किसी भी तरह से मुश्किल या अव्यवहारिक नहीं होगा। अधिनियम की धारा 16(1-क) के बल पर उपबंधों के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न करना संविधि के उद्देश्य, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को पराजित करेगा और अवांछनीय परिणाम उत्पन्न करेगा। संशोधित धारा के प्रावधानों को केवल आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। धारा 16 (1) (ए) आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करती है और ये इस संबंध में मूल प्रावधान हैं। धारा 16 (1 ए) के प्रावधान किसी भी मामले में नियामक और प्रक्रियात्मक हैं। वे एक पद्धति का प्रावधान करते हैं, जिसे आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए अपनाया जाना चाहिए। एक बार जब राष्ट्रपति की नियुक्ति धारा 16 (1) (ए) के प्रावधानों के अनुरूप और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक आदेश के अनुरूप की जाती है, तो यह स्पष्ट रूप से अन्य प्रावधानों का भी पर्याप्त अनुपालन होगा।

(39) हमारे लिए, स्पष्ट रूप से इन दो धाराओं के प्रावधानों के बीच कोई संघर्ष नहीं प्रतीत होता है क्योंकि वे अपने संबंधित क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। इसे दूसरे दृष्टिकोण से देखते हुए, अधिनियम की संशोधित धारा 16 (1-ए) के प्रावधानों को धारा 16 (1) (ए) के प्रावधानों के अनुरूप माना जाएगा ताकि

अधिनियम के वांछित उद्देश्य और इसे विनियमित करने वाले कानून को प्राप्त किया जा सके। इन प्रावधानों को आसानी से एक साथ समेटा और पढ़ा जा सकता है ताकि असुविधाजनक या कानूनी रूप से अवांछनीय परिणामों को रोका जा सके। लॉर्ड हर्शेल एल.सी. ने संकेत दिया, 'आपको कोशिश करनी होगी और उन्हें सामंजस्य स्थापित करना होगा जैसा कि आप कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आपको यह निर्धारित करना होगा कि कौन सा प्रमुख प्रावधान है, और अधीनस्थ प्रावधान कौन सा है और कौन सा दूसरे को रास्ता देना चाहिए। किसी एक प्रावधान को इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है कि दूसरे प्रावधान को अप्रभावी बनाया जा सके या यहां तक कि इसे निहित रूप से निरस्त भी किया जा सके। उन्हें एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और एक ठोस प्रावधान को वरीयता दी जाती है और अधीनस्थ प्रावधान मुख्य प्रावधानों में निहित कानून के मूल जनादेश के सम्मान में आते हैं। धारा 16 (1) (ए) के संदर्भ में राज्य आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति में धारा आईजी (आई-ए) के प्रावधानों की शायद ही कोई प्रभावी भूमिका होगी।

(40) प्रतिवादी-राज्य का तर्क दो प्रावधानों के बीच एक स्पष्ट असंगति या संघर्ष का संकेत देता है। जाहिर है, इस तरह का कुछ भी मौजूद नहीं है और एक व्याख्या, जो इस तरह के संघर्ष या असंगति पैदा करेगी, अनुचित व्याख्या होगी। इस स्तर पर, हम **अनवर हसन खान बनाम मोहम्मद**[19] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं। जहां अदालत ने निम्नानुसार कहा: -

> "यह तय है कि किसी अधिनियम के किसी विशेष प्रावधान की व्याख्या करने के लिए, क़ानून में उपयोग किए गए शब्दों और वाक्यांशों के अर्थ के आयात और प्रभाव को पाठ, विषय-वस्तु की प्रकृति और क़ानून के उद्देश्य और इरादे से इकट्ठा किया जाना चाहिए। यह एक क़ानून के निर्माण का एक प्रमुख सिद्धांत है कि संघर्ष से बचने और सामंजस्यपूर्ण निर्माण को अपनाकर इसके प्रावधानों का निर्माण करने का प्रयास किया जाना चाहिए। संविधि या उसके तहत बनाए गए नियमों को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और एक प्रावधान को दूसरे प्रावधान के संदर्भ में माना जाना चाहिए ताकि प्रावधान को प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के अनुरूप बनाया जा सके। सामंजस्यपूर्ण निर्माण का प्रसिद्ध सिद्धांत यह है कि प्रभाव सभी प्रावधानों को दिया जाना चाहिए और एक निर्माण जो "मृत पत्र" के प्रावधानों में से एक को कम

[19] (2001) 8 SCC 540

करता है, सामंजस्यपूर्ण निर्माण नहीं है। संविधियों की व्याख्या से संबंधित कानून के संबंध में यह न्यायालय भारत संघ बनाम वेदेम वास्को डी गामा के फिलिप टियागो डी गामा (1990) 1 एससीसी 277 (एससीसी पी 284, पैरा 16) में है।

"16. वैधानिक व्याख्या में अनिवार्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि विधायिका का इरादा क्या है। इस आशय का पता मुख्य रूप से विचाराधीन अधिनियमन के पाठ से लगाया जाना है। इसका मतलब यह नहीं है कि पाठ को इसकी प्रकृति या उद्देश्य के संदर्भ के बिना, केवल गद्य के एक टुकड़े के रूप में माना जाना चाहिए। एक क़ानून न तो एक साहित्यिक पाठ है और न ही एक दिव्य रहस्योद्घाटन है। शब्द निश्चित रूप से क्रिस्टल, पारदर्शी और अपरिवर्तित नहीं हैं जैसा कि श्री जस्टिस होम्स ने बुद्धिमानी से और ठीक से चेतावनी दी है (लोवेन बनाम आइजनर) (245 यूएस 418, 425 (1918) लर्न्ड हैंड, जे, ने समान रूप से जोरदार तरीके से कहा था: विधियों को यूक्लिड के प्रमेयों के रूप में नहीं, बल्कि उनके पीछे निहित उद्देश्य की कुछ कल्पना के साथ माना जाना चाहिए। (लेनिघ वी सहयोगी कोल कंपनी बनाम येनसैवेज) (218एफआर 547, 553)।

फिर भी **मैसर्स ब्रिटिश एयरवेज पीएलसी बनाम भारत संघ और अन्य**,[20] और **राजेंद्र प्रसाद यादव और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य**[21] के रूप में रिपोर्ट किए गए अन्य मामलों में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक क़ानून के प्रावधानों की व्याख्या करते समय, प्रत्येक प्रावधान को प्रभावी बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए और सभी प्रावधानों को इतने सामंजस्यपूर्ण ढंग से माना जाना चाहिए कि कोई भी प्रावधान अपना प्रभाव नहीं छोड़ता है। अपने संबंधित क्षेत्रों में अर्थ और संचालन।

(41) यह संविधि की व्याख्या का स्थापित सिद्धांत है कि जब विधायिका शक्ति की सीमा को निर्दिष्ट करती है, जिसका प्रयोग एक प्राधिकारी कर सकता है, तो ऐसी निर्धारित शक्ति का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं है। पूर्ण स्वतंत्रता और न्यायिक स्वतंत्रता के साथ ऐसे न्यायाधिकरणों के कामकाज के लिए विधायी इरादा अधिनियम की धारा 24-बी के प्रावधानों से स्पष्ट है। जिला और राज्य मंचों को राष्ट्रीय आयोग और/या राज्य आयोग के प्रशासनिक और पर्यवेक्षी नियंत्रण के तहत

---

[20] AIR 2000 SC 391

[21] (1997) 6 SCC 678

काम करना होता है, जैसा भी मामला हो, लेकिन इस स्पष्ट सावधानी के साथ कि इस तरह के नियंत्रण को किसी भी तरह से उनकी अर्ध-न्यायिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह इन आयोगों की स्वतंत्रता और न्यायिक कार्यकरण की स्वतंत्रता की सीमा है जिसका उद्देश्य विधायिका द्वारा किया गया है। इन परिसरों पर इस सिद्धांत को लागू करते हुए, यह किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है कि अधिनियम की धारा 16 (1-ए) के प्रावधानों के बल पर, समिति उच्च न्यायालय और राज्य के मुख्य न्यायाधीश में निहित शक्ति के साथ चयन की अपनी शक्ति को जोड़ सकती है।

(42) न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून की महिमा निश्चित रूप से यह परिकल्पना करती है कि आयोग के अध्यक्ष के न्यायिक मंच पर नियुक्ति अधिनियम की धारा 16 (1) (ए) के संशोधनों के अनुरूप की जानी चाहिए जिसमें मुख्य न्यायाधीश की राय को निश्चित प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस पद के लिए प्रस्ताव आम तौर पर मुख्य न्यायाधीश द्वारा शुरू किया जाना चाहिए, ताकि नियुक्तियों में अनावश्यक देरी से बचा जा सके। इस नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल दो आवश्यक घटकों यानी मुख्य न्यायाधीश और राज्य के बीच प्रशासनिक सामंजस्य को उपरोक्त प्रतिपादित कानून और पारस्परिकता के सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना चाहिए, ताकि इस प्रतिष्ठित पद पर सबसे उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त करने के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। वर्बा कम इफेक्टु एक्सिपिएन्ड संट फिर से विधियों की व्याख्या के कानून के लिए एक ज्ञात उपदेश है। इस तरह के नियम को लागू करने से न्यायालय पर क़ानून के प्रत्येक शब्द को प्रभावी बनाने का दायित्व बनता है और अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इसकी प्रयोज्यता और संचालन की स्वतंत्र रूप से अनुमति देता है। ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति केवल तभी संभव है जब ऐसी प्रक्रिया में शामिल संबंधित घटक/ प्राधिकरण कानून की निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्य करते हैं और अपने अधिकार का उपयोग करते हैं। हमें कुछ जोर देकर इसका उल्लेख करना चाहिए कि संघर्ष से बचा जाना चाहिए और प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए। असंगति का तत्व कानून की ठोस समझ और वैधानिक प्रावधानों को उनके संबंधित क्षेत्रों के दायरे में काम करने की अनुमति देने से गायब हो जाता है। हम पहले ही देख चुके हैं कि न तो दो वैधानिक प्रावधानों के बीच कोई संघर्ष है और न ही वे एक-दूसरे के लिए विनाशकारी या प्रतिकूल हैं। सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत पर निर्भरता मुख्य रूप से उत्तरदाताओं द्वारा उठाए गए विवाद के गुणों पर विचार करने के लिए प्रासंगिक है। हम पहले ही कह चुके हैं कि धारा 16 (1-ए) के प्रावधान अधिनियम की धारा 16 (1) (ए) के तहत विचार की

गई निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए किसी भी तरह से विनाशकारी नहीं हैं। अवांछनीय परिणामों से बचने और न्याय संस्थानों की गरिमा को बनाए रखने के लिए, धारा 16 (1) (ए) के प्रावधानों को आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के मामले में विवेकपूर्ण ढंग से लागू किया जाना चाहिए।

(43) हमारे समक्ष यह स्वीकार किया जाता है कि राज्य आयोग के अध्यक्ष 4 सितम्बर, 2003 को सेवानिवृत्त हो गए थे और तब से पदधारी को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण यह पद रिक्त पड़ा है। जहां बड़े पैमाने पर जनता को परेशान किया जा रहा है, वहां न्याय प्रशासन का हित भी प्रभावित हो रहा है।.

(44) इसलिए, हमें इन रिट याचिकाओं को स्वीकार करने और राज्य सरकार को यह निर्देश देने में कोई संकोच नहीं है कि वह इस निर्णय के अनुरूप इस निर्णय के अनुरूप सभी कदम उठाए ताकि राज्य आयोग के निवासी को इस निर्णय की घोषणा की तारीख से एक महीने के भीतर जल्द से जल्द और किसी भी मामले में नियुक्ति की जा सके। अत्यधिक विलंब से बचा जाना चाहिए और समय पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए हम आगे निर्देश देते हैं कि संबंधित अधिकारी कदम उठाएंगे और आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया उस तारीख से कम से कम तीन महीने पहले शुरू करेंगे जब मौजूदा राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। अत्यधिक विलंब से बचने और समय पर कार्रवाई करके न्याय के उचित प्रशासन का सामान्य पहिया प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी नियुक्तियां करने में अधिकारियों का दृष्टिकोण उद्देश्यपूर्ण, व्यापक और सूक्ष्म जगत विश्लेषण से रहित होना चाहिए। आम वादी की आवश्यकता संबंधित अधिकारियों पर एक दायित्व डालती है कि वे सटीकता और दृढ़ता के साथ कार्य करें। ऐसी नियुक्तियों में, समय सार है। इस प्रकार, हम यह भी आशा व्यक्त करते हैं कि भविष्य में राज्य आयोग के समक्ष लंबित मामलों के निपटान में विलंब से बचने के लिए पदधारी की सेवानिवृत्ति या अन्यथा के परिणामस्वरूप रिक्ति को भरने के लिए समय पर कदम उठाए जाएंगे।

(45) तदनुसार रिट याचिकाओं को अनुमति दी जाती है, हालांकि, पार्टियों को अपनी लागत खुद वहन करनी होगी।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक

उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रजत अरोड़ा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी